

contractor's employees are covered by the benefit provided under the Workmen's Compensation Act.

हिमाचल प्रदेश में सहकारी आन्दोलन

*२११६. { श्री भक्त वर्र्मन :
श्री म० रा० मुनिस्वामी :

क्या गृह-कार्य मंत्री १८ फरवरी, १९५८ के अतारंकित अदन संख्या ३३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में सहकारी आन्दोलन की जांच करने वाली समिति ने अपना कार्य में इस बीच क्या प्रगति की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बात्तार) : इस मामले में अभी तक कोई अन्तिम फैसला नहीं हुआ है। यह काम एक सीनियर अफसर को सौंपा जा रहा है।

Some Hon. Members: In English also.

Shri Datar: Matters have not been finalised so far. A Senior Officer is being deputed for this purpose.

श्री भक्त वर्र्मन : श्रीमन्, क्या यह सत्य है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने वहां के सहकारी आन्दोलन का अध्ययन करने के लिये बहुत पहले एक समिति नियुक्त की थी। और उस समिति ने अपनी कोई रिपोर्ट भी दी थी उसके बाद भी इतनी देरी क्यों होती चली जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : एक कमेटी पहले नियुक्त हुई थी। उसके चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया और यह काम अधूरा हो रह गया। दूसरे चेयरमैन रखे गये। उन्होंने कई महीनों के बाद कमेटी की मीटिंग की और फिर भी काम पूरा नहीं हो सका तो अब यह तय किया है कि हमारे एक अफसर श्री विश्वनाथन वहां जायें और जल्दी ही इस मामले को सब देख दाख कर तय कर दें क्योंकि बहुत दिनों से यह लम्बा चला आता है।

श्री भक्त वर्र्मन : क्या कोई अनुमान लगाया गया है कि देर से देर तक इस बारे में रिपोर्ट आ जायेगी ?

पंडित गो० ब० पन्त : देर करने का इरादा नहीं है। जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है इसको किया जायेगा।

Shri N. R. Munisamy: May I know if it is a fact that the successor submitted his report on the 14th or 16th December 1957? If so, will the hon. Minister be pleased to place it on the Table of the House?

Pandit G. B. Pant: No Committee report has been received.

श्री भक्त वर्र्मन : क्या मैं जान सकता हूँ कि इस बारे में जब अन्तिम फैसला हो जायेगा तो उस फैसले की एक प्रतिलिपि इस सदन की मेज पर भी रखी जायेगी और हिमाचल प्रदेश की टेरिटोरियल काउंसिल को भी उस पर विचार करने का मौका दिया जावेगा ?

पंडित गो० ब० पन्त : ऐसे मामलों में मामूली जाब्जा तो ऐसा है नहीं।

New Delhi Municipal Committee

*2117 { Shri Rameshwar Tantia:
Shri V. C. Shukla:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the set-up of the New Delhi Municipal Committee is being reorganised; and

(b) if so, the details of the new set-up?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Datar): (a) and (b). The question of reorganising the New Delhi Municipal Committee is under consideration.